Realisation of excise duty from Hindustan Lever Limited and Gesteners Limited

266. SHRI MUKHTIAR SINGH MALIK: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) what is the quantum of excise duty pending realisation at present against various units of Hindustan Lever Limited and Gesteners Limited;

(b) since when the amount is pending realisation; and

(c) the time by when these excise duties are likely to be realised from the above companies?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JANARDHAN POOJARI): (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Recovery of excse duty from Cadburys Inda Limited

267. SHRI MUKHTIAR SINGH MALIK: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) what are the details of the excise duty at present pending realisation from Cadburys India Limited, the manufacturers of Chocolates;

(b) since when the excise duty realisation pending against the company;

(c) whether any show-cause notice was issued for the speedy recovery of the amount; and

(d) if so, what are the details in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JANARDHAN POOJARI): (a) to (d) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Export of decapitated children's heads

268. SHRI MUKHTIAR SINGH MALIK:

SHRI SHANKER SINH VAGHELA:

Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-item which appeared in the 'Blitz' of 17th August, 1985 to the effect that kids under 10 are being abducted, drugged and decapitated for the export of their heads abroad for medical reasearch;

(b) whether it is also a fact that decapitated bodies are thrown into Ganga; and

(c) whether Government propose to put a complete ban on the export of human skeletons so as to save the lives of innocent children and if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI ARJUN SINGH): (a) Yes, Sir.

(b) No specific instances have come to notice.

(c) A complete ban on export of 'Human Skeletons and parts thereof has already been imposed with effect from the 19th August, 1985.

Constitution of wage board sugar industry

269. SHRI SHANKER SINH VEGHELA: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the State Governments have agreed to the constitution of a Wage Board for sugar industry; and

(b) what progress has been made in the constitution of the Wage Board and

what action has been taken by the various State Governments in this connection?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI T. ANJAIAH): (a) and (b) Information is being collected from the State Governments/Union Territory Administrations and the same will be laid on the Table of the House.

केन्द्रीय रेशम बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति

270. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या **वस्त्र** मंत्री 23 जुलाई, 1985 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 27 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय रेशम बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति की जा चुकी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका नाम, अर्हता और अनुभव क्या हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री **खुर्शीद आलम खान**) : (क) जी, अभी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

रेशम का उत्पादन

271. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस समय असम के मूंगा रेशम का उत्पादन समाप्त होने पर है तथा ऐरी रेशम के उत्पादन में भी कमी होती जा रही है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में उत्पादित मलबरी किस्म के रेशम के उत्पादन में भी कमी होती जा रही है ;

(ग) क्या टसर का उत्पादन भी नहीं के बराबर हो रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार रेशम उत्पादन के सर्वोपरि विकास के लिए क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री **खुर्शीद आलम खान**) : (क) तथा (ख) जी, नहीं ।

(ग) वर्ष 1984-85 के दौरान देश में टसर कच्चे रेशम के उत्पादन का भाग कुल गैर-शहतूती रेशम उत्पादन का 57 प्रतिशत रहा । 1980-81 के 265 मे० टन के स्तर से यह क्रमश: बढ़कर 1984-85 में 444 मे० टन हो गया ।

(घ) देश में कच्चे रेशम के उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से केन्द्रीय रेशम बोर्ड विशिष्ट विकास परियोजनाएं और साथ ही इस संबंध में राज्यों की सहायता के लिए केन्द्रीय परियोजनाएं क्रियान्वित करता रहा है। अब ऐसा प्रस्ताव है कि देश में रेशम उत्पादन के समग्र विकास के लिए 7वीं योजना के दौरान, केन्द्रीय रेशम बोर्ड के कार्यकलाप बढ़ा दिए जाएं । बोर्ड द्वारा इस समय क्रियान्वित की जा रही प्रमुख गहन कृत्रिम रेशम उत्पादन विकास परियोजनाएं निम्नोक्त प्रकार हैं :—

(1) विश्व बैंक की सहायता से कर्नाटक में गहन कृत्रिम रेशम उत्पादन विकास हेतु परियोजना ।

(2) राष्ट्रीय रेशम क्रीड़ा बीज परियोजना ।

(3) पश्चिम बंगाल के लिए गहन कृत्रिम रेशम उत्पादन विकास परियोजना ।

(4) अन्तरराज्यीय टसर परियोजना ।

(5) मूंगा बीज विकास परियोजना ।